नागरिक समीक्षा

माननीय न्यायमूर्ति पी. सी. पंडित के समक्ष

संयुक्त, पत्नी श्री प्रेम कुमार- याचिकाकर्ता

बनाम

प्रेम कुमार मदन, आदि,-प्रतिवादी

सिविल रिवीजन 380, 1974

2 नवंबर 1973.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V)-आदेश 33 नियम 1 और 2- "कंगाल"- भरण-पोषण की प्राप्ति में पत्नी द्वारा वाद का अर्थ एकमुश्त भत्ता - ऐसा भत्ता खर्च नहीं किया गया है और रखरखाव के लिए कोई पैसा उधार नहीं लिया गया है - मुकदमा - क्या फॉर्म पौप्रिस में दायर किया जा सकता है।

यह निर्णय लिया गया कि, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के नियम 1 से जुड़े स्पष्टीकरण के अनुसार, एक व्यक्ति तब कंगाल होता है जब उसके पास इस तरह के मुकदमे में मुकदमे के लिए कानून द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। या, जहां ऐसी कोई फीस निर्धारित नहीं है, जब वह अपने आवश्यक पहनने के परिधान और मुकदमे की विषय-वस्तु के अलावा एक सौ रुपये की संपत्ति का हकदार नहीं है। यह परिभाषा दो भागों में है. पहला भाग उस मामले पर लागू होता है जहां वाद के लिए कानून द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है और दूसरा भाग उस मामले से संबंधित है जहां ऐसी कोई फीस निर्धारित नहीं है। ऐसे मामलों में, जो पहले भाग के अंतर्गत आते हैं, केवल उस व्यक्ति को कंगाल घोषित किया जाएगा, जिसके पास निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस भाग में प्रयुक्त शब्द "साधन" है न कि "संपत्ति"। इसलिए, यह देखना होगा कि क्या उसके पास पर्याप्त संपत्ति है, जो उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम कर सकती है, या क्या उसके पास इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त "साधन" है। उसके पास अपेक्षित राशि हो या न हो, लेकिन यदि वह अपेक्षित धन या कुछ संपत्ति जुटा सकता है, तो उसे कंगाल नहीं माना जाएगा, क्योंकि तब उसके पास कोर्ट-फी का भुगतान करने के लिए "साधन" है।

यह भी निर्णय लिया गया कि पत्नी के हाथ में एकमुश्त भरण-पोषण राशि, न तो उसके भरण-पोषण के लिए खर्च की गई या उसके भरण-पोषण के कारण किसी बकाया का भुगतान, न ही भरण-पोषण के लिए उधार लिया गया कोई पैसा, पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है और वह उसका एकमात्र हिस्सा बन जाता है। वह संपत्ति जिसका उपयोग मुकदमा दायर करने के लिए आवश्यक अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

संहिता के आदेश 33 के नियम 1 के स्पष्टीकरण के तहत उसे कंगाल नहीं ठहराया जा सकता और वह पुपरिस के रूप में मुकदमा दायर नहीं कर सकती।

1919 के अधिनियम IX की धारा 44 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, करनाल के 7 मार्च, 1973 के आदेश में संशोधन के लिए याचिका, जिसमें मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। एक कंगाल और वादपत्र पर अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए एक महीने का समय दिया गया और उस पर आने का आदेश दिया गया 7 अप्रैल, 1973.

याचिकाकर्ता की ओर से वकील वाई. पी. गांधी।

प्रतिवादियों की ओर से वकील एस. पी. गोयल।

पंडित, जे.-

यह श्रीमती द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका है के आदेश के विरुद्ध प्रेम कुमार मदन की पत्नी संयुक्ता, ट्रायल जज ने आदेश 33, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उसके आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने दहेज के सामान की वसूली के लिए अपने पति पर कंगाल के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसका उसने वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेख किया था। वैकल्पिक रूप से, उसने रुपये का दावा किया। उन वस्तुओं का मूल्य 26,090 है।

(2) इस याचिका के निर्धारण के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य ये हैं। दोनों पक्षों की शादी मई, 1966 में करनाल में हुई थी। वे दोनों लगभग तीन साल तक साथ रहे और फिर उनके बीच मतभेद पैदा हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उसके अनुसार, उसके पति ने उसे छोड़ दिया और करनाल में अपने पिता, जो एक वकील थे, के साथ रहने लगी। सितंबर 1969 में, पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दिल्ली में उसके खिलाफ एक याचिका दायर की। यह लगभग दो साल तक लंबित रही और उसके बाद इसे वापस ले लिया गया। सितंबर/अक्टूबर 1971 में, उन्होंने उसके खिलाफ फिर से दिल्ली में अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव के लिए एक याचिका दायर की। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त याचिका अभी भी लंबित थी, जब वर्तमान कंगाल आवेदन 14 दिसंबर, 1971 को करनाल में दायर किया गया था। पत्नी के अनुसार, उसके पास कोई चल या अचल संपत्ति नहीं थी और वह कोर्ट-फी का भुगतान करने में असमर्थ थी और इसलिए, उसे उक्त आवेदन दायर करना पड़ा।

(3) इसका पति ने विरोध किया, जिसका मामला यह था कि उसकी पत्नी कंगाल नहीं थी और उसके पास अदालत की फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन थे। वह जानबूझकर सारे तथ्य कोर्ट के सामने नहीं लायी थी। रुपये की राशि. उसके लिए 3,480 रुपये जमा किए गए थे और यह दिल्ली में अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी की अदालत में पड़ा हुआ था। रुपये का एक चेक. वास्तव में उसे 2,480 रुपये जारी किए गए थे, जो कि, पति के अनुसार, उसने वसूल कर लिया होगा और बाकी पैसे अभी भी पड़े हुए थे। उनका दिल्ली में ओरिएंटल बैंक ऑफ

कॉमर्स में एक बचत निधि खाता भी था और रु. उसके खाते में 400 थे। उसे छोड़ते वक्त वह सारे गहने और कीमती कपड़े अपने साथ ले गई थी।

(4) अपने आवेदन के समर्थन में, स्वयं गवाह-बॉक्स में जाने के अलावा, उन्होंने अपने पिता, श्री ज्ञान चंद गुलाटी, वकील को भी पेश किया। ए.डब्ल्यू. 1, श्री प्रेम दत्त, अधिवक्ता, ए.डब्लू. 2 और श्री एस.एस. नलव... सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, ए.डब्ल्यू. 3. खंडन में, पति अकेले आर.डब्ल्यू. 1 के रूप में साक्ष्य में उपस्थित हुआ।

(5) सबूतों पर विचार करने के बाद, ट्रायल जज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पति ने रुपये जमा किए थे। अपनी पत्नी को भुगतान के लिए मार्च 1970 से अब तक दिल्ली कोर्ट में 5,480 रु. चुकाए हैं, सिर्फ रुपये लिये गये. 1,000. उसने यह नहीं बताया कि उक्त राशि उसे कब प्राप्त हुई, लेकिन शेष राशि रुपये से अधिक थी। उसके भुगतान के लिए अभी भी 4,000 रुपये जमा थे। यह राशि रुपये के रखरखाव का प्रतिनिधित्व करती है। 200 प्रति माह, जो पति को पत्नी को देना पड़ता था। रुपये थे. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दिल्ली में पत्नी के बचत बैंक खाते में 400 रुपये जमा हैं। लेकिन, उनके मुताबिक, उन्होंने रुपये निकाले थे. सितंबर 1969 के बाद 400। उन्होंने उक्त वापसी की सही तारीख का उल्लेख नहीं किया। उनके अनुसार, खाते में शेष राशि रु. 10 या रु. 12. विद्वान न्यायाधीश ने यह भी पाया कि उसका भरण-पोषण उसके पिता द्वारा किया जा रहा था और वह उसे दी गई भरण-पोषण की राशि में से कुछ भी खर्च नहीं कर रही थी। आगे यह पाया गया कि पति ने अपनी पत्नी के कपड़े, बर्तन आदि की एक सूची दी थी, जिसके अनुसार, वह उससे चार्ज ले सकती थी। इन वस्तुओं में एक रेडियो-ग्राम, एक सिलाई मशीन, एक गोदरेज अलमारी, प्रेस, केतली, डिनर सेट और अन्य बर्तन और बिस्तर शामिल थे। हालाँकि, उसने ये सामान पति से नहीं लिया था। विद्वान न्यायाधीश ने माना कि यद्यपि यह सच है कि वे चीजें पत्नी ने नहीं ली थीं, लेकिन पति ने उन्हें वापस करने की पेशकश की थी और इसलिए, वे पत्नी के नियंत्रण में थे, जिसका उपयोग वह भुगतान के लिए कर सकती थी। कोर्ट-फी. पत्नी ने यह नहीं बताया कि उसने रुपये खर्च किये या नहीं. पति से मिले 1,000 रु. उसके बचत बैंक खाते से 400 रुपये निकाले गए। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इस परिस्थिति को भी ध्यान में रखते हुए कि कलेक्टर ने पत्नी के मामले को कंगाल के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने की सिफारिश नहीं की थी, विद्वान न्यायाधीश ने 7 मार्च, 1973 को उसके आवेदन को खारिज कर दिया और उसे भुगतान करने के लिए एक महीने का समय दिया गया। वादपत्र पर न्यायालय शुल्क. इस आदेश को उन्होंने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी है।

(6) आर.डब्लू. 1 के रूप में पति के साक्ष्य के अनुसार, वह रुपये का रखरखाव दे रहा था। मार्च 1970 से 3 फरवरी 1973 को गवाही देने के दिन तक उन्होंने अपनी पत्नी को प्रति माह 200 रुपये जमा किये थे। कोर्ट में 5,480 रुपये दिए, जिसके संबंध में वह रसीदें अपने साथ लाए थे। उन प्राप्तियों का विवरण इस प्रकार था:

13 अक्टूबर 1970 को 1.490,

22 अप्रैल 1971 को 990.

10 जनवरी 1972 को 800 रु.

1 फरवरी 1972 को 200 रु.

12 अप्रैल, 1972 को 400,

16 मई 1972 को 200 रु.

16 अगस्त 1972 को 400 रु.

20 अक्टूबर 1972 को 400 रु.

22 नवंबर 1972 को 400 रु.

18 जनवरी 1973 को 200 रु.

(7) इन रसीदों से पता चलेगा कि पति ने रुपये जमा किये थे. 14 दिसंबर, 1971 से पहले 2,480, जब पत्नी द्वारा कंगाल आवेदन दायर किया गया था और बाकी, यानी, रु। बाद में 3,000 रुपये जमा कर दिए गए, लेकिन 7 मार्च, 1973 को इस आवेदन के फैसले से पहले। पत्नी के साक्ष्य के अनुसार, उसे पति से भरण-पोषण मिल रहा था, लेकिन इसे भुनाया नहीं गया था। यह रखरखाव रु. शुरुआत में 160 रुपये प्रति माह और बाद में यह रु. 200. लेकिन उसे रुपये के अलावा कोई राशि नहीं मिली थी। 1,000, जो उसे कुछ महीने पहले ही मिले थे। उन्होंने 1 दिसंबर, 1972 को अपना साक्ष्य दिया और इसका मतलब चैट रु. दिसंबर 1972 से कुछ महीने पहले उसने 1,000 रुपये लिए थे। इसलिए, यह राशि उसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33, नियम 2 के तहत आवेदन दायर करने के कई महीनों बाद प्राप्त हुई थी। उसने अपने साक्ष्य में यह भी कहा (कि सितंबर 1969 के बाद, उसने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दिल्ली से 40 रुपये के अलावा किसी भी बैंक से कोई राशि नहीं निकाली थी। इसलिए, यह राशि उसके दाखिल करने की तारीख से बहुत पहले निकाली गई थी) कंगाली का आवेदन। दहेज में से जो सामान पति उसे लौटाने की पेशकश कर रहा था, वह अभी भी उसके पति के पास था। दोनों वकील इस बात पर सहमत हैं कि अदालत की फीस, जो उसकी पत्नी को वादपत्र पर देनी थी, वह थी रु. 2,197.60 पैसे। ये तथ्य होने के कारण, निर्धारण के लिए प्रश्न यह है कि क्या अर्जित न्यायाधीश ने प्युपेरिस के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए पत्नी के आवेदन को खारिज करने में सही था।

(8) कौन दरिद्र है, इसकी परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के नियम 1 से संलग्न स्पष्टीकरण में दी गई है। यह पढ़ता है: "एक व्यक्ति तब कंगाल होता है जब उसके पास ऐसे मुकदमे के लिए कानून द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, या जहां ऐसी कोई फीस निर्धारित नहीं होती है, जब वह एक सौ रुपये की संपत्ति का हकदार नहीं होता है उसके आवश्यक परिधान और सूट की विषय-वस्तु के अलावा।"

9) जैसा कि स्पष्टीकरण से देखा जाएगा, इसके दो भाग हैं। पहला भाग उस मामले पर लागू होता है जहां वाद के लिए कानून द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है और दूसरा भाग उस मामले से संबंधित है जहां ऐसी कोई फीस निर्धारित नहीं है। ऐसे मामलों में, जो पहले भाग के अंतर्गत आते हैं, केवल उस व्यक्ति को कंगाल घोषित किया जाएगा, जिसके पास निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। उन मामलों की आवश्यकताओं का उल्लेख करना अनावश्यक है, जिन पर दूसरा भाग लागू होता है, क्योंकि, माना जाता है कि, वर्तमान मामले में, वाद-पत्र के लिए शुल्क कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं तो हमारा क्या मतलब है? यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस भाग में प्रयुक्त शब्द "साधन" है न कि "संपत्ति"। दूसरे शब्दों में, देखने का प्रश्न यह नहीं है कि क्या उसके पास पर्याप्त संपत्ति है, जो उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम कर सकती है, बल्कि यह है कि क्या उसके पास इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त साधन हैं। उसके पास अपेक्षित धन हो या न हो, लेकिन यदि वह किसी संपत्ति पर अपेक्षित धन जुटा सकता है, तो उसे कंगाल नहीं माना जाएगा।

(10) अगला सवाल यह है कि किस तारीख को यह माना जाए कि क्या उसके पास निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन हैं? क्या यह आदेश 33, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख पर है, या उसके निर्णय की तारीख पर है?

(11) इस मुद्दे पर कुछ उच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक राय में मतभेद है। कुछ, अर्थात. कलकत्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालयों ने माना है कि आवेदन दाखिल करने की तारीख ही वास्तविक तारीख है और जबकि अन्य, उदाहरण के लिए, मद्रास और पटना उच्च न्यायालय, एक अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं। इस मामले में इस बिंदु पर चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि अगर दाखिल करने की तारीख देखी जाए, तो भी यह सामान्य आधार है कि पति ने रुपये जमा किए थे। उक्त तिथि से पहले भरण-पोषण के रूप में 2,480 रुपये और यह राशि अदालत-शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगी, जो रुपये थी। 2,197.60 पैसे. था।

(12) कुछ न्यायालयों के बीच मतभेद भी है मुकदमे में दावा की गई संपत्ति का मूल्य है या नहीं के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कंगाली, इसी बात का जिक्र कर रहा हूं. क्योंकि, कोर्स के दौरान मेरे समक्ष तर्कों में विद्वान वकील द्वारा इसका तर्क दिया गया प्रतिवादी के लिए कि पति ने वस्तुओं की एक सूची दी थी, जो मुकदमे का विषय था, उसके अनुसार, उसकी पत्नी उससे प्रभार ले सकती थी, हालाँकि उसने उस प्रस्ताव का लाभ नहीं उठाया था और उन वस्तुओं को उससे ले लिया था। इस बिंदु पर भी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जमा की गई राशि अर्थात् रु. प्रतिवादी के अनुसार 2,480, वादपत्र पर अपेक्षित न्यायालय-शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था।

(13) इसलिए विचार करने के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या उक्त राशि, अर्थात् रु। 2,480, को यह पता लगाने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है कि वादी कंगाल था या नहीं। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह राशि, निश्चित रूप से, उसके भरण-पोषण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे पति रुपये की दर से जमा कर रहा था। शुरुआत में

160 और बाद में रु. की दर से. पहले की दो याचिकाओं में 200-एक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए, जिसे सितंबर 1969 में दायर किया गया था, और लगभग दो साल बाद वापस लेने के लिए, और दूसरी अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव के लिए। , जो सितंबर/अक्टूबर 1971 में पति द्वारा लाया गया था, और अभी भी लंबित था - इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया जा सका कि क्या उसके पास निर्धारित अदालत-शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन थे या नहीं। दलील यह थी कि उक्त राशि उसके भरण-पोषण के लिए थी और इसे उसी पर खर्च किया जाना था, न कि अदालत की फीस का भुगतान करने के लिए।

(14) दोनों वकील सहमत हैं कि इस बिंदु पर कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क में दम होगा यदि यह दिखाया जा सके कि उसके पति द्वारा जमा की गई भरण-पोषण की राशि खर्च की जा रही थी। उसे उसके भरण-पोषण के लिए. कोई ऐसे मामले की कल्पना कर सकता है जहां पत्नी के पास किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं है और रखरखाव का भुगतान पति द्वारा महीने की शुरुआत में किया जाता है और वह इसे अपने दैनिक खर्चों के लिए खर्च करती है। एक अन्य मामले की भी कल्पना की जा सकती है, जहां समान परिस्थितियों में, रखरखाव राशि बाद में जमा की जाती है, लेकिन इस बीच, पत्नी अपने भरण-पोषण के लिए पैसे उधार लेती रहती है और ऋण का भुगतान तब किया जाता है जब रखरखाव राशि बाद में जमा की जाती है। पति द्वारा. दयाल कौर बनाम उजागर सिंह और अन्य (ए.आई.आर. 1972 पी एंड एचआर 18) मामले में मेरे पास ऐसी स्थिति से निपटने का अवसर था। वहां पति द्वारा अपनी पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के लिए रकम जमा की जाती थी और पत्नी उधार में पैसे लेती थी और जब भरण-पोषण के पैसे, उसके पति द्वारा भुगतान किया गया, कर्ज चुकाया गया। पत्नी और मेरी बेटी दोनों अपना भरण-पोषण ऋण पर करते थे और वे पति द्वारा जमा की गई भरण-पोषण राशि से अपना कर्ज़ चुकाते थे। उन परिस्थितियों में, मैंने माना कि मुख्य राशि को यह पता लगाने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है कि क्या उसके पास कानून द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन थे और क्या वह एक गरीब थी या नहीं।

(15) हालाँकि, वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। यह साक्ष्य में है कि याचिकाकर्ता के पिता करनाल में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वह ही थे, जो पूरे समय उनका भरण-पोषण कर रहे थे। याचिकाकर्ता गवाह के सामने पेश हुई और उसने कुछ अन्य लोगों के अलावा अपने पिता को भी गवाह के रूप में पेश किया। उनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि उसने अपने भरण-पोषण के लिए कोई पैसा उधार लिया था, जिसका भुगतान पति द्वारा जमा की गई भरण-पोषण राशि से किया जाना था। इतना ही कहा गया है कि आज तक याचिकाकर्ता के पिता ही उसका भरण-पोषण कर रहे हैं। भरण-पोषण राशि, जो कंगाली आवेदन दाखिल करने की तारीख से पहले जमा की गई है, इसलिए, उसकी एकमात्र संपत्ति बन गई है, जिसमें से उसे किसी का कुछ भी देना नहीं है। यह रकम पूरी तरह से याचिकाकर्ता के नियंत्रण में है और इसका उपयोग वादपत्र पर अपेक्षित अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, यह कहना संभव नहीं है कि उसके पास निर्धारित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

ऐसा होने पर, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के नियम 1 के स्पष्टीकरण के अर्थ में उसे कंगाल नहीं माना जा सकता है।

(16) जो मैंने ऊपर कहा है, उसके मद्देनजर यह याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। हालाँकि, उसने वादपत्र पर आवश्यक अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए तीन महीने की अवधि की अनुमति दी।

*****

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा